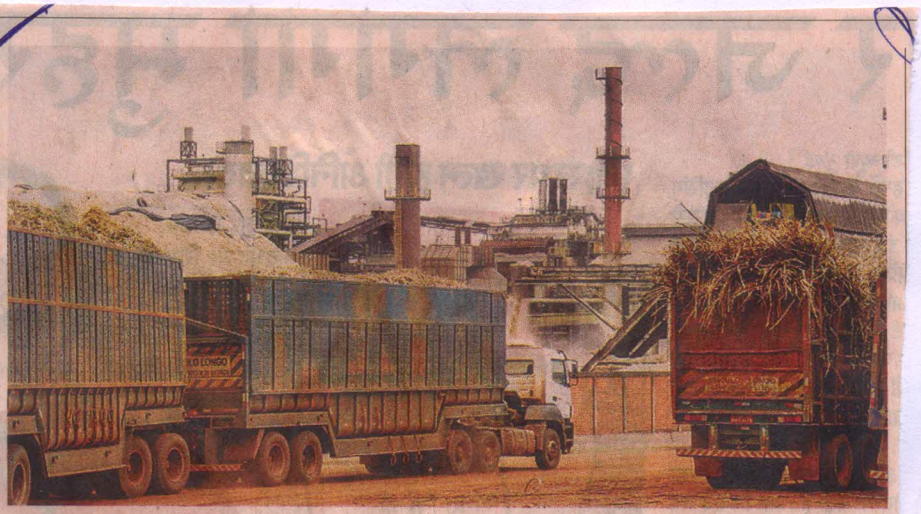

मिलों को UP सरकार राहत देने को तैयार!

टैक्स और कमीशन में शुगर मिलों को छूट देने पर हो रहा विचार

[मनमोहन राय *लखनऊ*]

उत्तर प्रदेश में शुगर सेक्टर से जुड़ी समस्या का कुछ हल निकलने की उम्मीद बनी है। राज्य सरकार ने मंगलवार को शुगर इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ दूसरे दौर की मीटिंग की। इसका मकसद मिलों की ओर से जल्द गन्ने की प्रीपेमेंट और पेराई शुरू करना पक्का करना था।

सरकार ने गन्ने के लिए 280 रुपये प्रति क्विंटल के एसएपी को घटाने और 3,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की मिलों की डिमांड ठुकरा दी है, लेकिन टैक्स और कमीशन हटाने के तौर पर कुछ देने का इरादा जाहिर किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ हुई मीटिंग में बजाज हिंदुस्तान के कुशाग्र बजाज, बलरामपुर चीनी मिल्स के विवेक सरावगी, डीएससीएल के अजित श्रीराम और बिड़ला ग्रुप के सी एस नोपानी जैसे इंडस्ट्री के बड़े नाम शामिल थे।

यादव ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशंस शुरू करना मिलों की ड्यूटी है। उन्होंने मौजूदा संकट का हल निकालने के तरीकों पर चर्चा की।

मिल मालिकों ने हायर प्रॉडक्शन कॉस्ट और मार्केट में चीनी के कम दाम का हवाला देते हुए गन्ने का एसएपी घटाकर 225 रुपये प्रति क्विंटल करने की डिमांड की। उनका कहना था कि अगर यह नहीं होता तो सरकार को 3,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देनी चाहिए। इस पर राज्य सरकार ने अपने खजाने पर दबाव होने की बात कही और सब्सिडी देने से मना कर दिया। इसके साथ ही सरकार ने एसएपी घटाने से भी पूरी तरह इनकार किया।

हालांकि, दोनों पक्षों ने इंडस्ट्री को कुछ छूट देने पर विचार किया। इसमें सोसाइटी कमीशन और चीनी पर एंट्री टैक्स हटाना शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रति क्विंटल गन्ने पर 6.30 रुपये सोसाइटी कमीशन लगाती है, जो राज्य के खजाने में नहीं जाती और इसे हटाया जा सकता है। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्र ने बताया कि इसके अलावा मीटिंग में उत्तर प्रदेश में बेची जाने वाली चीनी के इनवॉयस प्राइस पर 2 फीसदी एंट्री टैक्स को हटाने पर भी विचार किया गया।

SAP घटाने की मांग खारिज

- मिलों के साथ दूसरे दौर की मीटिंग में सरकार ने गन्ने के लिए 280 रुपये प्रति क्विंटल के एसएपी को घटाने और 3,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की मिलों की डिमांड ठुकरा दी है
- मीटिंग में दोनों पक्षों ने शुगर इंडस्ट्री को कुछ छूट देने पर विचार किया। इसमें सोसाइटी कमीशन और चीनी पर एंट्री टैक्स हटाना शामिल है

इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि इन दो मांगों को लेकर कुछ पॉजिटिव फैसला आने से उन्हें कुछ राहत मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से भी इंडस्ट्री के हित में कुछ उपाय किए जाने की उम्मीद है। अगर यह जल्द होता है मिलें इस सप्ताह के अंत तक शुरू की जा सकती हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में प्राइवेट चीनी मिलों ने सरकार से कहा था कि बढ़ते घाटे और गन्ने के ऊंचे एसएपी की वजह से इस सीजन में पेराई शुरू नहीं करेंगी। इन मिलों ने अपने गेट के बाहर नोटिस लगाकर सूचना दी है कि वे इस साल ऑपरेट नहीं करेंगी और किसानों को गन्ना कहीं ओर बेचना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में शुगर मिलों के बंद होने की वजह से राज्य सरकार पर किसानों और इंडस्ट्री से जुड़े अन्य लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा है। यादव ने 21 नवंबर को बरेली में हुई रैली में कहा था कि उन्होंने गन्ने के 280 रुपये प्रति क्विंटल के एसएपी की घोषणा की है और अब वह एक ऐसे समाधान के लिए काम करेंगे, जिससे किसान और मिलें दोनों काम कर सकें।

Economic Times
27/11/13